an>

Title: Need to accord sanction for the pending irrigation projects in Rajasthan.

श्री ओम बिरला (कोटा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के हाड़ौती संभाग की कई महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना केन्द्रीय जल आयोग में लंबित हैं। इन योजनाओं के स्वीकृत होने से कोटा और बारा की अधिकांश ज़मीनों पर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा। जहां लोग फ्लोराइडयुक्त पानी पी रहे हैं, वहां पेयजल की योजनाओं के माध्यम से लोगों को साफ पीने का पानी भी मिलेगा।

महोदय, मैं आपके माध्यम से हाड़ौती की परवन सिंचाई परियोजना, जिसकी अनुमानित लागत 5,000 करोड़ रुपए है, इसे राÂट्रीय सिंचाई परियोजना में शामिल करने के लिए अनुरोध कर रहा हूं। इसी तरीके से काली सिंध-II की परियोजना, जिसकी लागत 700 करोड़ रुपए है, वह जल आयोग में विचाराधीन है। इसको भी बहुत जल्द स्वीकृति दी जाए।

महोदय, बूंदी जिला मेरे लोक सभा क्षेत्र में आता है। वÂान 2010 में बूंदी जिले में गरदड़ा बांध के क्षतिग्रस्त होने के कारण हजारों बीघा ज़मीन परती पड़ी हुई है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है केन्द्रीय जल आयोग के अंदर गरदड़ा बांध की जो ड्राइंग और डिज़ाइन लंबित पड़ी हुई है, इसे भी जल्दी से जल्दी स्वीकृत किया जाए, ताकि गरदड़ा बांध का निर्माण हो सके।

महोदय, राजस्थान के तीन नदियों को जोड़ने के प्रस्ताव के डी.पी.आर. बनाने का प्रस्ताव लंबित है। इससे पार्वती, काली सिंध नदियों का सरप्लस पानी बनास, गंभीर और पार्वती नदियों में आएगा, जिससे आठ जिलों के लोगों को सिंचाई और पेयजल का पानी उपलब्ध होगा। उसी तरीके से, जायका स्कीम-II के अंतर्गत 3,461 करोड़ रुपए के विभिन्न तालाबों, नहरों के जीर्णोद्धार के ऋण के प्रस्ताव भी लंबित पड़े हुए हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इनको भी जल्दी स्वीकृति दी जाए, ताकि राजस्थान के खेतों को पानी मिल सके और लोगों को पेयजल सुविधा उपलब्ध हो सके।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra is permitted to associate with the issue raised by Shri Om Birla.